www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 30 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण

विनम्रता सभी गुणों की जननी है

सरकार का इंतजार

महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी भाजपा और शिवसेना के बीच बढ़ती खींचतान को ही बयान कर रही है। ऐसा लगता है कि यह खींचतान लंबी खिंचेगी, क्योंकि जहां शिवसेना इस पर अड़ी है कि ढाई-ढाई साल के फार्मूले के तहत दोनों दल के नेता बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनें वहीं भाजपा ऐसी किसी व्यवस्था को स्वीकार करने से इन्कार कर रही है। गठबंधन सरकार के गठन के दौरान सहयोगी दलों के बीच कुछ न कुछ खींचतान होती ही है, लेकिन महाराष्ट्र में वह कुछ ज्यादा ही विद्रूप होती जा रही है। समस्या केवल यह नहीं कि सरकार गठन को लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है, बल्कि यह भी है कि दोनों दलों के बीच मतभेद कटुता का रूप ले रहे हैं। यह कटुता दोनों दलों के संबंधों में खटास ही पैदा करेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में दोनों दल एक-दूसरे से छिटक चुके हैं। पिछला विधानसभा चुनाव दोनों दल अलग-अलग लड़े थे। राजनीतिक मजबूरी के चलते दोनों फिर से करीब आए। अब उनमें फिर से दुराव पैदा हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण शिवसेना की ओर से यह प्रदर्शित किया जाना है कि वह भाजपा पर जितने ज्यादा तीखे हमले करेगी, उसका दावा उतना ही मजबूत होगा।

यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है कि शिवसेना भाजपा पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकाने का काम करे। शिवसेना की ओर से यह संकेत दिया जाना एक तरह की धमकी ही है कि अगर उसकी शर्तें न मानी गईं तो वह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पाले में जा सकती है। फिलहाल यह नहीं लगता कि वह अपनी इस धमकी को लेकर गंभीर है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। सत्ता की ललक में राजनीतिक दल किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। पता नहीं शिवसेना क्या करेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बारी-बारी से मुख्यमंत्री पद संभालने की व्यवस्था एक नाकाम फार्मूला है। यह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक-दूसरे के प्रति अविश्वास पर टिका होता है। ऐसा कोई फार्मूला शासन व्यवस्था के लिए एक बोझ ही साबित होगा। इसका कोई मतलब नहीं कि कोई सरकार ढाई साल तक एक तरह से चले और शेष ढाई साल दूसरी तरह से। अगर ऐसा नहीं होना है तो फिर इसका औचित्य ही क्या है कि बारी-बारी से दो मुख्यमंत्री ढाई-ढाई साल सरकार चलाएं? यह समय उन तौर-तरीकों पर विचार करने का है जिनसे महाराष्ट्र की जनता की अपेक्षाओं को सही तरह से पूरा किया जा सके। यह देखना दयनीय है कि इसके बजाय सत्ता की ज्यादा मलाई हासिल करने को लेकर खींचतान हो रही है।

निर्मल गंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार निर्मल गंगा अभियान उत्तराखंड में परवान चढ़ने लगा है। हालांकि गोमुख और बदरीनाथ से ऋषिकेश के बीच गंगा का पानी काफी हद तक स्वच्छ है, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में हालात इतने सुकूनदायक नहीं हैं। नमामि गंगे के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान जनवरी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दोनों शहरों में गंगा में गिर रहे ज्यादातर नाले टैप कर दिए गए हैं और शेष भी जल्दी टैप हो जाएंगे। निःसंदेह इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं तो गोमुख से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के पानी की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी की है। बावजूद इसके हरिद्वार में गंगा के पानी के कतिपय नमूनों में कुछेक स्थानों पर फीकल कॉलीफार्म (मल-मूत्र) भी पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ समय से स्थिति में सुधार आया है। दरअसल देखा जाए तो यह समस्या का सिर्फ एक पहलू है। गंगा को यदि निर्मल रखना है तो इस नदी के साथ ही सहायक नदियों की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। आम तौर पर देखने में आया है कि उत्तरकाशी हो या देवप्रयाग अथवा रुद्रप्रयाग और बदरीनाथ। गंगा तट पर बसे ज्यादातर कस्बों और शहरों में अक्सर किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं। हालांकि नदियों के किनारे कूड़े डालने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस पर अभी पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। पॉलीथिन के ढेर इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं। यह समस्या बरसात में और भी गंभीर हो जाती है। तब यह कूड़ा नदियों में पहुंच जाता है। इसके लिए जिलों में प्रशासन ने जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया, लेकिन एक दो दिन के कार्यक्रम से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए लगातार सक्रिय रहने की जरूरत है। इसके अलावा नगर निकायों को भी गंगा स्वच्छता में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। अक्सर देखने में आया है कि निकायों ने नियम-कानून तो बना दिए हैं, लेकिन उनके पास इन नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। उत्तराखंड गठन के बाद से निकाय क्षेत्रों को विस्तार तो हुआ, बावजूद इसके स्टॉफ में कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके साथ ही राजस्व को लेकर भी निकायों की स्थिति दयनीय है। जाहिर है निकायों को मजबूत किए बिना गंगा स्वच्छता किसी चुनौती से कम नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को भी जागरूक करने की जरूरत है। ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटक भी हिमालय में बड़ी मात्रा में कूड़ा छोड़ आते हैं। इसको लेकर भी गंभीर होने की जरूरत है।

कूटनीति को नई धार देता भारत

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि दोस्ताना रिश्ते निभाने में वह एक कदम आगे चलने को तैयार है, पर अपने आंतरिक मामलों में किसी का दखल उसे बर्दाश्त नहीं होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय सऊदी अरब दौरे पर हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस दौरे के साथ ही उन्हें अंकारा भी जाना था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के कश्मीर पर बिगड़े बोल से कुपित पीएम मोदी ने अपना तुर्की दौरा रद कर दिया। एर्दोगन ने न केवल कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया, बल्कि चीन और मलेशिया के साथ मिलकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को काली सूची में जाने से भी बचाया। मानों इतना ही काफी नहीं था, एर्दोगन ने यह भी कहा कि वह आगे भी वैश्विक मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे। मोदी के तुर्की दौरे का मकसद था दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम देना, लेकिन एर्दोगन की बदजुबानी ने इस मुहिम को परवान चढ़ने से पहले ही फुस्स कर दिया। इससे पहले तक भारत-तुर्की संबंधों में सब कुछ सही दिख रहा था। बीते पांच वर्षों में मोदी और एर्दोगन तीन बार मुलाकात कर चुके हैं ।

भारत सरकार मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से भी खफा है। उन्होंने भी कश्मीर में भारत के कदम की आलोचना करते हुए उसे पाक के साथ मिलकर मसला सुलझाने की वकालत की। इससे नाराज सरकार मलेशिया से पाम ऑयल आयात बंद करके इंडोनेशिया, अर्जेंटीना या यूक्रेन जैसे किसी अन्य देश से मंगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक ताकत का इतना बखूबी इस्तेमाल किया है जिसकी स्वतंत्र भारत के इतिहास में मिसाल मिलनी मुश्किल है। शासन कला में व्यापार एवं वाणिज्य बेहद अहम पहलू होते हैं। तुर्की और मलेशिया के मसले को मोदी ने सही तरीके से संभाला। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। दोनों जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और पड़ोसियों के साथ तनातनी के चलते सुरक्षा के मोर्चे पर भी हालात सही नहीं हैं। ऐसे परिदृश्य में भारत के साथ रिश्तों को तल्ख बनाना इन देशों के लिए कूटनीतिक रूप से समझदारी नहीं कही जा सकती।

तुर्की का क्षेत्रफल, 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से वह भारत के तकरीबन पांचवें हिस्से के बराबर है, मगर वह चार प्रमुख चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों- बाल्कन, कॉकेशस, पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। एनाटोलियन प्रायद्वीप पर तुर्की काला सागर, भूमध्य सागर और एजियन सागर से घिरा है। एनाटोलिया ऐसा केंद्रीय बिंदु है जिसकी धुरी पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप मिलते हैं। वैश्वीकरण के अलावा इन क्षेत्रों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों और संघर्षरत देशों के साथ तुर्की की नजदीकी उसकी अहमियत और बढ़ा देती हैं। वहीं 3,28,550 वर्ग किलोमीटर में फैला मलेशिया भारत के लगभग दसवें हिस्से के बराबर है। यह दक्षिणपूर्व एशिया में मुख्यभूमि से लेकर द्वीप समूहों तक एक प्रमुख भू-रणनीतिक पट्टी के रूप में स्थित है। दक्षिणपूर्व एशिया के मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी बिंदु पर मलेशिया प्रायद्वीप है जबकि पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर है जहां से दक्षिण चीन सागर 600 किलोमीटर दूर है। इसके साथ लगे मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से पूर्व और पश्चिम के बीच अधिकांश व्यापार होता है जिसके किनारे मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच विभाजित हैं। इन सभी के एक दूसरे से तल्ख रिश्ते हैं। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत इन दोनों क्षेत्रों में एक अहम अंशभागी है। ऐसे में वह अपने आंतरिक मामलों पर तीखी टिप्पणियां नहीं पचा सकता।

अवधेश राजपूत

तुर्की के राष्ट्र निर्माता मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने अपने देश को आधुनिक बनाने के मकसद से 29 अक्टूबर 1923 को खलीफा शासन की समाप्ति का एलान कर तुर्की को गणतंत्र घोषित किया। इसके साथ ही वहां धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता और आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तुर्की ने शरीया कानूनों को आधिकारिक दायरे से बाहर रखकर मुस्लिम बहुल देशों में अपने लिए एक अलग पहचान गढ़ी, लेकिन एर्दोगन अब उसी पहचान को मिटाने पर तुले हैं। हालांकि वहां अभी तक धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचा कायम है, लेकिन उनके राज में तुर्की के हालिया घटनाक्रम खतरनाक बदलावों की ओर संकेत करते हैं। तुर्की ने बीते 9 अक्टूबर को सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती को 'जिहाद' करार दिया जिससे इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सवालिया निशान लगते हैं। सरकारी धार्मिक मामलों के निदेशालय ने तुर्की की सभी 90,000 मस्जिदों को लाउडस्पीकरों से उस संदेश के प्रसारित करने का आदेश दिया जो इस्लाम की निंदा पर हिंसक होने के लिए उकसाने वाली कवायद है। तुर्की के समाज पर शरीया को थोपने के लिहाज से यह अहम पड़ाव है। एर्दोगन सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया है। इस्लाम की निंदा या उसके उचित अनुपालन न होने पर कड़ाई की जा रही है। तुर्की राष्ट्रीय पुलिस नवंबर 2017 से धार्मिक टिप्पणियों की ऑनलाइन निगरानी कर रही है और उसे जहां भी इस्लाम पर कोई टिप्पणी खटकती है तो वह तुरंत कार्रवाई करती है। सार्वजनिक रूप से इस्लाम की आलोचना अपराध बन गई है। सोशल मीडिया में इस्लाम पर नकारात्मक टिप्पणियों या हास-परिहास को लेकर लोगों पर मुकदमें चलाए जा रहे हैं।

तुर्की ने इसी महीने की शुरुआत में सीरिया से लगी सीमा पर कुर्दों के खिलाफ हमला बोल दिया। तुर्किश वायु सेना ने सीमावर्ती इलाकों पर बम बरसाए। इसके चलते 1,30,000 लोग विस्थापन के लिए मजबूर हुए। वहीं सीरिया में करीब 70 नागरिकों की जान चली गई तो तुर्की में भी 20 लोग मारे गए। एर्दोगन की विदेश नीति को नियो-ऑटोमन नीति कहा जा रहा है। वहां सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान तुर्की-सीरिया सीमा पर सीरियन-कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स को ताकत हासिल करने से रोकने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत को भी मानवाधिकारों के ऐसे उल्लंघन के मुद्दे को मुखरता से उठाने से नहीं हिचकना चाहिए।

मोदी सरकार मलेशिया को भी अपनी नाखुशी को लेकर सख्त संदेश देना चाहती है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय भावनाओं को समझते हुए भारतीय व्यापारियों ने मलेशियाई पाम ऑयल के अघोषित बहिष्कार का फैसला किया। बीते शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशियाई विदेश मंत्री सैफुद्दीन अब्दुल्ला को अपने सख्त रुख से अवगत कराया। भारत विश्व में खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में अगर वह दूसरे देशों से आयात की संभावनाएं टटोलेगा तो मलेशिया को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भारतीय कूटनीतिक तंत्र ने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि दोस्ताना रिश्तों को निभाने में वह एक कदम आगे चलने को तैयार है, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में किसी का दखल उसे बर्दाश्त नहीं होगा।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

उदारवादियों का विचार-विमर्श

राजीव सचान

क्या यह संभव है कि बगदादी को मजहबी विद्वान बताने वाले यह न जानते हों कि वह कितना खूंखार था?

दुनिया के सबसे वहशी आतंकी अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने पर दुनिया ने इसके बावजूद राहत की सांस ली कि न तो इस्लामिक स्टेट का खात्मा होने जा रहा है और न ही अन्य अनेक जिहादी संगठनों का। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस्लामिक स्टेट का सरगना अल बगदादी आधुनिक काल का सबसे घिनौना और बर्बर आतंकी था। उसने मध्ययुगीन बर्बरता को भी मात दे रखी थी। उसने लोगों के बेरहमी से सिर तो कलम किए ही, उन्हें जलाकर, लोहे के पिंजरे में कैद करने के बाद पानी में डुबोकर, ऊंची इमारतों से फेंककर और बूचड़खानों में काट-काट कर भी मारा। इसी तरह उसने महिलाओं को यौन दासियों में तो तब्दील किया ही, उनकी नीलामी भी की और उनसे खुलेआम दुष्कर्म भी। उसकी बर्बरता के किस्से रोंगटे खड़े करने वाले थे, फिर भी दुनिया भर के तमाम देशों के युवक उसके संगठन में शामिल होने के लिए इराक-सीरिया चले आए। इनमें अच्छी-खासी संख्या उनकी थी जो पढ़े-लिखे और यूरोप-अमेरिका में सुविधा संपन्न जीवन जीने वाले थे। माना जाता है कि इसकी एक वजह उन्हें यौन दासियां उपलब्ध कराना और साथ ही खिलाफत को फिर से कायम करने का सपना दिखाना था। आश्चर्यजनक रूप से इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वालों में युवतियां भी थीं। बगदादी की बर्बर विचारधारा से आकर्षित जो युवा इराक-सीरिया नहीं जा सके वे अपने-अपने देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। इसके चलते यूरोप, अमेरिका के साथ-साथ अन्य अनेक देशों में आतंकी हमले कर खौफ पैदा किया गया। बगदादी के उन्मादी आतंकियों की नृशंसता का शिकार इराक गए 39 भारतीय भी बने।

बगदादी सरीखे महापातकी आतंकी के मारे जाने की खबर दुनिया भर में प्रमुखता पानी ही थी। उसने पाई भी, लेकिन एक खबर कुछ इस तरह से थी-कट्टर मजहबी विद्वान अल बगदादी की 48 साल की उम्र में मौत। यह खबर अमेरिका के बड़े अखबार 'वाशिंगटन पोस्ट' की वेबसाइट पर आई तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। अमेरिकी प्रशासन से जुड़े लोगों और पत्रकारों के अलावा अन्य अनेक लोगों ने इस खबर की जमकर खिंचाई की। इसी के साथ वाशिंगटन पोस्ट का मजाक उड़ाने वाले ट्वीट किए जाने लगे, लेकिन क्या यह महज हास-परिहास का विषय था? यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बगदादी को मजहबी विद्वान के तौर पर पेश करने का काम किसी गफलत के चलते नहीं हुआ। यह सोच-समझ कर ही किया गया होगा, क्योंकि पहले इस समाचार का शीर्षक कुछ इस तरह था-इस्लामिक स्टेट के सरगना अल बगदादी की मौत। फिर कुछ सोचकर, पता नहीं क्या सोचकर, उसे मजहबी विद्वान बता दिया गया। जब इसे लेकर वाशिंगटन पोस्ट की फजीहत होने लगी तब फिर से शीर्षक बदल कर अल बगदादी को इस्लामिक स्टेट का सरगना कहा गया। इसके साथ ही यह सफाई भी पेश की गई कि उसे मजहबी विद्वान बताने वाली खबर का वह मतलब नहीं था जो समझा गया। पता नहीं इस स्पष्टीकरण के जरिये क्या स्पष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन बगदादी के मारे जाने पर उसे खूंखार आतंकी बताने में वाशिंगटन पोस्ट के अलावा अन्य अनेक पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने भी परहेज किया। यह परहेज उन मीडिया संस्थानों की ओर से किया गया जो लिबरल या लेफ्ट लिबरल के तौर पर जाने जाते हैं। लिबरल यानी उदारवादी, लेकिन आम जनता के लिए यह समझना कठिन है कि आखिर किसी बर्बर आतंकी को मजहबी विद्वान बताने वाले खुद को लिबरल या उदारवादी कैसे कह सकते हैं? वास्तव में इन्हें कुदारवादी या ऐसे ही किसी अन्य शब्द से परिभाषित किया जाना बेहतर होगा।

निःसंदेह ऐसा नहीं हो सकता कि बगदादी को मजहबी विद्वान बताने वाले यह न जानते हों कि वह कितना घृणास्पद था। यह जानते हुए भी उन्होंने उसके प्रति नरमी दिखाई तो शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने के कारण ही। संभवतः वे यह नहीं चाहते होंगे कि ट्रंप को बगदादी के मारे जाने का किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिले। यह तब और स्पष्ट हुआ जब वाशिंगटन पोस्ट में ही इस आशय का एक लेख आया कि ट्रंप का यह दावा सही सही नहीं कि बगदादी की मौत एक कायर की तरह हुई, क्योंकि उसने तो अमेरिकी सैनिकों की गिरफ्त में जाने के बजाय खुद को विस्फोट के जरिये उड़ाने का फैसला किया। इसके जरिये यही कहने की कोशिश की गई कि बगदादी ने बहादुरी दिखाई। एक अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े नीति विश्लेषक और स्तंभकार मैक्स बूट के इस लेख की भी तीखी आलोचना हुई। जब आलोचना ज्यादा तीखी हुई तब इस लेख की उस पंक्ति में हेरफेर किया गया और यह हास्यास्पद सफाई दी गई कि उससे यह प्रतीति हो रही थी कि बगदादी साहसी था। इन दिनों अमेरिकी मीडिया में ऐसे विचारों की भरमार है जिनके जरिये यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप को बगदादी के मरने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यह आकलन एक बड़ी हद तक सही जान पड़ता है। बगदादी मरा है, लेकिन उसकी विचारधारा नहीं। बावजूद इसके इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि ट्रंप के प्रति अपनी नापसंदगी प्रकट करने के लिए एक खूंखार आतंकी के प्रति नरमी बरती गई। उदारवादियों और वस्तुतः कुदारवादियों का यह व्यवहार अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। क्या कोई 'एंड दे हैंग्ड याकूब' शीर्षक को भूल सकता है जो मुंबई बम धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकी याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद एक अंग्रेजी दैनिक की पहली खबर बना था। यह महज अपवाद नहीं, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद एक अन्य अंग्रेजी दैनिक की खबर इस शीर्षक से थी-'कार बांबर किल्स 37 ट्रूपर्स।' यह तो याद ही होगा कि आतंकी बुरहान वानी को किस तरह स्कूल हेडमास्टर का बेटा बताया गया था।

निःसंदेह उदारवादियों उर्फ कुदारवादियों को निवार्चित शासकों को नापसंद करने और उनकी निंदा-भर्त्सना करने का अधिकार है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि वे अपने इस अधिकार का इस्तेमाल आतंकियों के प्रति हमदर्दी प्रकट करने या फिर उनकी कुत्सित हरकतों की अनदेखी करने में करें।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय का मूल्य

जीवन की परिभाषा समय है, क्योंकि जीवन समय से बनता है। समय का सदुपयोग जीवन का उपयोग है, समय का दुरुपयोग जीवन को नष्ट करना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निरंतर अज्ञात दिशा में जाकर विलीन होता रहता है। हमारा कर्तव्य है समय का पूरा-पूरा सदुपयोग करें। समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति-साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिलता। संत कबीर ने चेतावनी देते कहा है-'कल पर अपने काम को न टालें। आज करना है, उन्हें आज पूरा कर लें।

प्रत्येक काम का अवसर होता है। अवसर वही है, जब वह काम सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व समाप्त हो जाता है तथा बोझ बढ़ता जाता है। जवानी के समय को विश्राम के नाम पर नष्ट करना घोर मूर्खता है, क्योंकि यही वह समय है, जिसमें मनुष्य जीवन का, भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। विश्राम अवश्य करें। अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका समय निश्चित करें। समय बड़ा मूल्यवान है। उसे किफायत से व्यय करें। जितना समय-धन को बचाकर उसे आवश्यक उपयोगी कार्यों में लगाएंगे, उतनी व्यक्तित्व की महत्ता एवं हैसियत बढ़ेगी। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालें।

आदत पड़ जाने पर स्वयं ही बड़ा आनंद आएगा। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें एक मिनट का अंतर न आए। तभी अपने समय का पूरा-पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अधिकार जमाता है। कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी, तकलीफ आदि में विश्राम करना बुरा नहीं है, लेकिन आंखें खुलीं तो तुरंत अपने काम में लगें।

मुकेश ऋषि

भुखमरी दूर करने का मौलिक तरीका

अनीश कुमार

जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरा बल नहीं दिया जाएगा तब तक देश से भुखमरी की समस्या को दूर करना कठिन बना रहेगा

विश्व बैंक ने कहा है कि 1990 के बाद अब तक भारत अपनी गरीबी दर को आधे स्तर पर ले जाने में सफल रहा। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भुखमरी और कुपोषण के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं नेपाल से भी पीछे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत 117 देशों में 102वें स्थान पर है। अगर देश में गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ रहे हैं तो भुखमरी के कारण देश फिसड्डी क्यों हो रहा है। अर्थशास्त्र का यह दोहरा अर्थ समझ पाना बहुत मुश्किल है। मानव विकास के मोर्चे पर भारत की विफलता का यह मामला तब सबके सामने है जब दुनिया भर में भूख और गरीबी मिटाने का मौलिक तरीका क्या हो उसे बताने वाले भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबल दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी साफ है कि भारत में 6 से 23 महीने के सिर्फ 9.6 फीसद बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकृत भोजन हो पाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा और भी कमजोर मात्र 6.4 बताया गया है। यूनिसेफ भी कह रहा है कि दुनिया में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि कद के अनुरूप वजन के मामले में भारतीय बच्चे सबसे फिसड्डी, सबसे पीछे और यमन जैसे युद्ध झेलकर जर्जर हुए देश के बच्चों से भी भारत पीछे हैं।

हालांकि भारत में मृत्यु दर, कम वजन और अल्प पोषण जैसे संकेतकों में सुधार दिखता है। ऐसे में सवाल है कि जब विश्व बैंक भारत को गरीबी के मामले में तुलनात्मक उठा हुआ मानता है तो फिर भुखमरी क्यों है? गौरतलब है कि 1989 की लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट में गरीबी 36.1 फीसद बताई गई थी तब विश्व बैंक भारत में यही आंकड़ा 48 फीसद मानता था और इसमें यह भी देखा गया कि 2400 कैलोरी ऊर्जा ग्रामीण और 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने वाले शहरी लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। मौजूदा समय में आर्थिक दृष्टि से देखें तो 1.90 डॉलर प्रतिदिन कमाने वाले गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं। अब समझने वाली बात यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी जरूरी आवश्यकताएं क्या इतने में पूरी हो सकती हैं? जाहिर है गरीबी से ऊपर उठने का जो स्तर तय किया गया है वह निहायत न्यून प्रतीत होता है।

जीवन को बाजार के भाव पर आंका जाय तो यह दर बहुत कम है। शायद यही कारण है कि भारत गरीबी रेखा से ऊपर के मामले में बेहतर आंकड़े की ओर है। जबकि हंगर इंडेक्स के आंकड़े उसे फिसड्डी साबित कर रहे हैं। जब तक वैकल्पिक रास्ता नहीं अपनाया जाएगा मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पूरा बल नहीं दिखाया जाएगा तब तक भुखमरी के आंकड़े समेत गरीबी को दूर करने की संतोषजनक स्थिति प्राप्त करना कठिन बना रहेगा। सरकार को बेरोजगारी की कतार को कम करना चाहिए। अवसर की प्रतीक्षा में भी जो हैं उनके साथ सामाजिक न्याय हो ताकि जब गरीबी घटे तो भुखमरी भी घटे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

न दृष्टि, न इतिहास

भारतीय दृष्टि वाला इतिहास शीर्षक आलेख में हृदयनारायण दीक्षित ने ठीक ही लिखा है कि अब अंग्रेजी सत्ता, संस्कृति, सभ्यता व वामपंथ को समर्थन देने वाले इतिहास कर्म का पोस्टमार्टम जरूरी हो गया है। पश्चिमी या इस्लामी दृष्टि से लिखे गए भारत के इतिहास को पीएन ओक ने 'धृष्टतापूर्ण मनोरंजन' बताया है। नेपोलियन का कहना था कि चूंकि इतिहास विजेताओं द्वारा ही लिखवाया जाता है, इसलिए वह एक सत्यता-रहित दंतकथा जैसा प्रतीत होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुरुदेव टैगोर ने लिखा है-सौभाग्यशाली हैं वे देश जो चिरंतन स्वदेश को अपने इतिहास में ही ढूंढ लेते हैं। बचपन में इतिहास ही उनका परिचय अपने देश से करा देता है। अंग्रेजों के बच्चे जानते हैं कि उनके बाप-दादों ने व्यापार किया, देश जीते और दुनिया पर शासन किया। वे स्वयं भी उनकी तरह धन-गौरव, रण-गौरव और विजय-गौरव के अधिकारी बनना चाहते हैं, पर भारत के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनके पुरखों ने न तो व्यापार किया, न देश जीते, न कोई साम्राज्य खड़ा किया। यही जानने के लिए है भारत का इतिहास। किंतु उनके पुरखों ने क्या किया, ये वो नहीं जानते। इस विकृत इतिहास को पढ़ने से कोई प्रेरणा हमें-हमारे बच्चों को प्राप्त नहीं होती। जब इस विकृति को दूर कर सही तथ्यों से युक्त नया इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने विद्यार्थियों को दिया तो वामपंथियों ने भगवाकरण का हौवा खड़ा कर दिया। इसकी पोल न्यायपालिका में खुल गई, वैसे ही जैसे भगवा आतंकवाद की हवा निकली। विकृत इतिहास में आर्यों को प्रथम आक्रमणकारी बताया जा रहा था, गुरु तेगबहादुर, शिवाजी, महाराणा प्रताप को हत्यारे और डकैत बताया गया था। जहां तक आर्य-आक्रमण की बात है तो उसके संबंध में तो बाबा साहब आंबेडकर ने ही लिखा कि यह सिद्धांत इतना वाहियात है कि काफी पहले इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए था। तो अब देशवासियों को प्रेरणा देने वाले भारतीय दृष्टि से लिखे गए इतिहास का वक्त आ पहुंचा है। हमारी इतिहास पुस्तकें इतिहास बताने वाली हों, इति न हास अर्थात ऐसा नहीं हुआ समझाने वाली नहीं।

अजय मित्तल, मेरठ

मेलबाक्स

आदर्श स्थापित करे दिल्ली

देश के विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली इसलिए पलायन करते हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। काम के साथ-साथ तमाम सुख-सुविधाएं उन्हें मिल सकें। लेकिन साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में हो रहे इजाफे को देखकर अब लोग सोचने पर विवश हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन लोगों ने कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए दिवाली पर खूब पटाखे जलाए। परिणाम स्वरूप दिल्ली की आबोहवा प्रदूषण के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। यह स्थिति तब है जब सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित कर दिया था कि रात आठ से दस के बीच ही पटाखे जलाए जाएंगे, वह भी ग्रीन पटाखे। सोचने वाली बात यह है कि हमारा वास्तविक समाज किस अंधविश्वास का पालन कर रहा है। जो एक स्वस्थ जीवन को चुनौती दे रहा है। जिस दिल्ली को देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श स्थापित करनी चाहिए थी, वह दिल्ली प्रदूषण का संदेश दे रही है। अब तो ऐसा लगता है जैसे जहरीली हवा में घुट-घुट कर जीवन जीना ही दिल्लीवासियों की नियति बन गई है।

मिथिलेश कुमार

सादगी भरी हो त्योहार की खुशी

प्रत्येक वर्ष दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो जाता है, जो एक स्वस्थ्य मनुष्य के जीवनकाल को प्रभावित करता है। इस खतरनाक प्रदूषण के कारण लोगों में सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत रहती है। लेकिन इससे कुछ सीखने के बजाय हम हर बार एक ही गलती को दोहराते जाते हैं। प्रशासन के लाख सतर्कता और पटाखा जलाने के लिए समय निर्धारित करने के बाद भी कुछ लोगों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। उन्होंने पटाखे जलाकर दिवाली का जश्न मनाया। इस वर्ष बेशक प्रदूषण का स्तर विगत 5 वर्षों में सबसे कम रहा हो, लेकिन इस समय भी प्रदूषण का जो स्तर है वह काफी खतरनाक है। यह मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। इससे जाहिर है कि लोगों द्वारा ही ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों ही जिंदगी इस प्रदूषण की बलि चढ़ जाए। आखिर लोग इस बात को क्यों नहीं मानते कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरनाक है?

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।